



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 2, February 2022

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.569

9940 572 462

6381 907 438

ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

भारतीय अर्थवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां

डॉ सुरेंद्र सिंह चारण

सह-आचार्य, अर्थशास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय, दौसा.

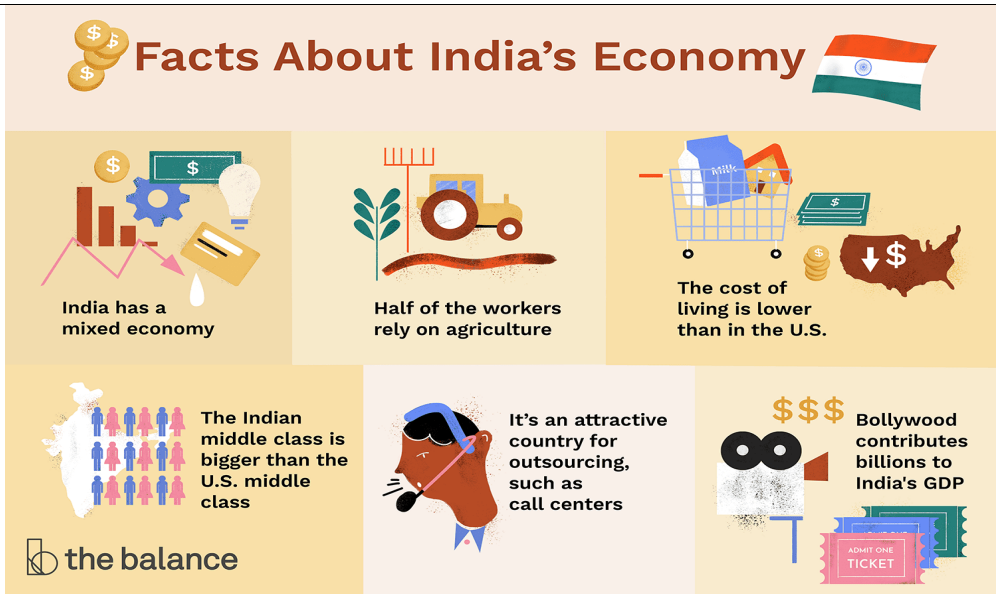
सार

पहले से ही धीमी रफ्तार से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को वैश्विक महामारी कोरोना ने एक व्यापक धक्का दिया. वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने उद्योग धंधों पर अस्थायी ताला लगा दिया, जिसके फलस्वरूप देश ने आजादी के बाद से सबसे बड़ी मंदी को देखते हुए जीडीपी विकास दर में 23.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की. साल 2021 की शुरुआत में देश जहां एक ओर कोरोना वैक्सीन के वितरण की तैयारियों में लगा है, वहीं आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य होने की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को आने वाले साल में अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार तक कई मुद्दों पर व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. आइए एक नजर डालते हैं इन्हीं चुनौतियों पर. च्वाइस ब्रोकिंग के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बागड़िया का कहना है, 'चार्ट पैटर्न पर ICICI बैंक और SBI दोनों के ही स्टॉक पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 580 रुपये के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए SBI के शेयरों को मौजूदा स्तर पर खरीद सकता है। स्टॉक पर 520 रुपये का स्टॉप लॉस बनाए रखना चाहिए।' उन्होंने कहा कि मीडियम टर्म में 600 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। अगर ICICI बैंक के शेयरों की बात करें तो कोई भी व्यक्ति मौजूदा मार्केट प्राइस पर इस बैंकिंग स्टॉक को 800 से 820 रुपये तक के शॉर्ट-मीडियम टर्म टारगेट के लिए खरीद सकता है। स्टॉक पर 770 रुपये पर स्टॉप लॉस बनाए रखना चाहिए। सुमित बागड़िया भी SBI और ICICI बैंक में SBI के शेयरों को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने बताया है कि 31 दिसंबर 2021 को खत्म तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 167.41 फीसदी बढ़ा है। इस अवधि में IRCTC को 208.8 करोड़ रुपये का तिमाही मुनाफा हुआ है। इससे पिछले साल की समान अवधि में सरकार के मालिकाना हक वाली कंपनी IRCTC को 78.08 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर 2021 तिमाही में कंपनी का मुनाफा सितंबर तिमाही से भी ज्यादा रहा है। सितंबर 2021 तिमाही में कंपनी को 158.57 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि, पिछले एक महीने में IRCTC के स्टॉक से मिलने वाला रिटर्न निगेटिव रहा है।

परिचय

कोरोना वैक्सीन का वितरण : अमेरिका और ब्रिटेन जैसे धनी देशों ने अपनी जनता को कोरोना वायरस वैक्सीन देनी शुरू कर दी है, मगर भारत के लिए टीकाकरण की आगे की राह बहुत उज्ज्वल नहीं दिखाई दे रही है. भारत में फाइजर-बायोएनटेक और मॉडर्ना वैक्सीन को लेकर दुर्लभ आपूर्ति, मुश्किल परिवहन और उचित कोल्ड चेन की कमी जैसे कारणों की वजह से टीकाकरण अभियान में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.[1,2]

130 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए दो वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से विकसित व सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) की ओर से तैयार की जा रही कोविशिल्ड, भारत बायोटेक लिमिटेड की ओर से तैयार की जा रही कोवैक्सीन अभी भी निर्माताओं या सरकार के नियंत्रण में नहीं होने वाले कारकों के कारण एक दूर का सपना दिखाई दे रही हैं.



सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) अदार पूनावाला ने कहा है कि भारत को अगले साल कोविड वैक्सीन के वितरण के लिए 80,000 करोड़ रुपये के बड़े फंड की आवश्यकता होगी.

केंद्र सरकार ने 2 जनवरी से देशभर में कोविड वैक्सीन के लिए ड्राई रन चलाने का फैसला किया है. वैक्सीनेशन के लिए लगभग 96,000 वैक्सीनेटरों को प्रशिक्षित किया गया है. प्रशिक्षकों के राष्ट्रीय प्रशिक्षण में 2,360 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है और 719 जिलों में जिला स्तर के प्रशिक्षण में 57,000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है.

बजट : कोरोना महामारी के बाद 1 फरवरी को देश का आम बजट प्रस्तुत होने जा रहा है. इसकी तैयारियों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही 15 से अधिक बैठके की हैं, जिनमें 9 हितधारक समूहों के 170 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

वित्त मंत्री ने इस बार एक अभूतपूर्व बजट पेश करने का ऐलान किया है. देखना दिलचस्प होगा कि मंदी की चपेट में आए देश को राहत देने के लिए सरकार के बजट में क्या खास होने वाला है.

हालांकि विशेषज्ञों ने वेतनभोगी वर्ग को इस बजट से ज्यादा उम्मीदे नहीं रखने को कहा है, क्योंकि व्यक्तिगत आयकर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है.[3,4]

वित्तीय योजना और निवेश सलाहकार फर्म मनी मंत्रा के संस्थापक विरल भट्ट ने कहा कि इस बजट से केवल एकमात्र लाभ अपेक्षित है कि किसी नए कर का बोझ न डाला जाए.

दिसंबर 2021 तिमाही में IRCTC को ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू 140.7 फीसदी बढ़कर 540.21 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में IRCTC का रेवेन्यू 224.37 करोड़ रुपये था। वहीं, टोटल एक्सपेंस बढ़कर 275 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। आईआरसीटीसी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मंगलवार को 0.38 फीसदी की तेजी के साथ 838.75 रुपये के स्तर पर बंद हुए हैं। कंपनी बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड के भुगतान के लिए 18 फरवरी रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। अगर सेगमेंट के आधार पर रेवेन्यू की बात करें तो कैटरिंग सर्विसेज का रेवेन्यू 117 फीसदी बढ़कर 104 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कैटरिंग सर्विसेज से मिलने वाला रेवेन्यू 48 करोड़ रुपये था। इंटरनेट टिकटिंग से मिलने वाला रेवेन्यू 118 फीसदी बढ़कर दिसंबर 2021 तिमाही में 312 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 143 करोड़ रुपये था। टूरिज्म सेगमेंट से मिलने वाला रेवेन्यू दिसंबर 2021 तिमाही में 353 फीसदी बढ़कर 68 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इस सेगमेंट से 15 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था।



विचार – विमर्श

रोजगार : रोजगार सृजन का मुद्दा 2021 में भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बना रहेगा.[5,6]

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, मौजूदा योजनाओं को नये स्वरूप में ढालना और नई नियुक्तियों में तेजी लाना जैसे कुछ मुद्दे हैं जो 2021 में चुनौती बनकर खड़े होंगे.

इसके अलावा अगले साल एक अप्रैल से चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन होगा, जिससे औद्योगिक संबंधों में सुधार की दिशा में एक नई शुरुआत होगी और अधिक निवेश जुटाने में मदद मिलेगी.

कोविड-19 महामारी के चलते ये साल कार्यबल के साथ ही नियोक्ताओं के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा है. सरकार ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया, जिसका आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा और इसके चलते बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों को अपने मूल स्थान की ओर पलायन करना पड़ा.

कई प्रवासी मजदूरों ने अपनी नौकरी खो दी और उन्हें अपने मूल स्थानों से काम पर वापस लौटने में महीनों लग गए[7,8]



विदेशी व्यापार : कोरोना महामारी के बाद से ही यह उम्मीद जतायी जा रही है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत का योगदान बढ़ेगा. किंतु इस पर कोई उत्साहजनक विकास अभी तक नहीं दिखा है.

कोरोना वायरस के केंद्र के रूप में विख्यात होने के बाद कई वैश्विक कंपनियों का चीन से मोह भंग होने की आशंका थी. कई सर्वे में कहा गया कि कोविड-19 का एक बड़ा परिणाम यह है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चीन से दूसरी अर्थव्यवस्थाओं यानी देशों की ओर जा रही है. और इस कदम से भारत को लाभ होगा और आने वाले समय में विनिर्माण का अच्छा खासा हिस्सा चीन से भारत का रुख करेगा.

हालांकि, भारत की ओर आने वाले अवसरों को भुनाने के लिए देश के विनिर्माण तंत्र को मजबूत किए जाने की जरूरत है. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने कई उपाये किए हैं ताकि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को सुधारने के लिए कदम उठाये जा सके.[9,10]

इसके अलावा लंबे समय से अटका हुआ भारत-अमेरिका के बीच लघु व्यापार समझौते को भी पूरा करना एक चुनौती होगी.

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच 2020 की शुरुआत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के साथ हुई थी. विस्वाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लघु व्यापार समझौता नहीं हो पाया इसके बावजूद दोनों देशों के बीच पूरे साल रणनीतिक भागीदारी जोशपूर्ण बनी रही.

2021 अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शायद दोनों देशों को भागीदारी को अधिक व्यापक बनाने का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध करायेगा.

परिणाम

बैंक सुधार : रिजर्व बैंक की रेपो दर ताजा कटौती के बाद 5.75 प्रतिशत हो गयी गयी है। इससे रिवर्स रेपो दर 5.50 प्रतिशत पर आ गयी है। यह उम्मीद की जा रही है कि बैंक इस कटौती का लाभ अपने ग्राहकों को देंगे जिससे मकान, वाहन और अन्य कर्ज की मासिक किस्तें कम होंगी। नये साल में बैंकों के सामने फंसे कर्ज की समस्या से निपटना मुख्य चुनौती होगी. कई कंपनियों खासतौर से सूक्ष्म, लघु एवं मझौली (एमएसएमई) इकाइयों के समक्ष कोरोना वायरस महामारी से लगे झटके के कारण मजबूती से खड़े रहना संभव नहीं होगा, जिसकी वजह से चालू वित्त वर्ष की शुरुआती तिमाहियों के दौरान अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखी गई.

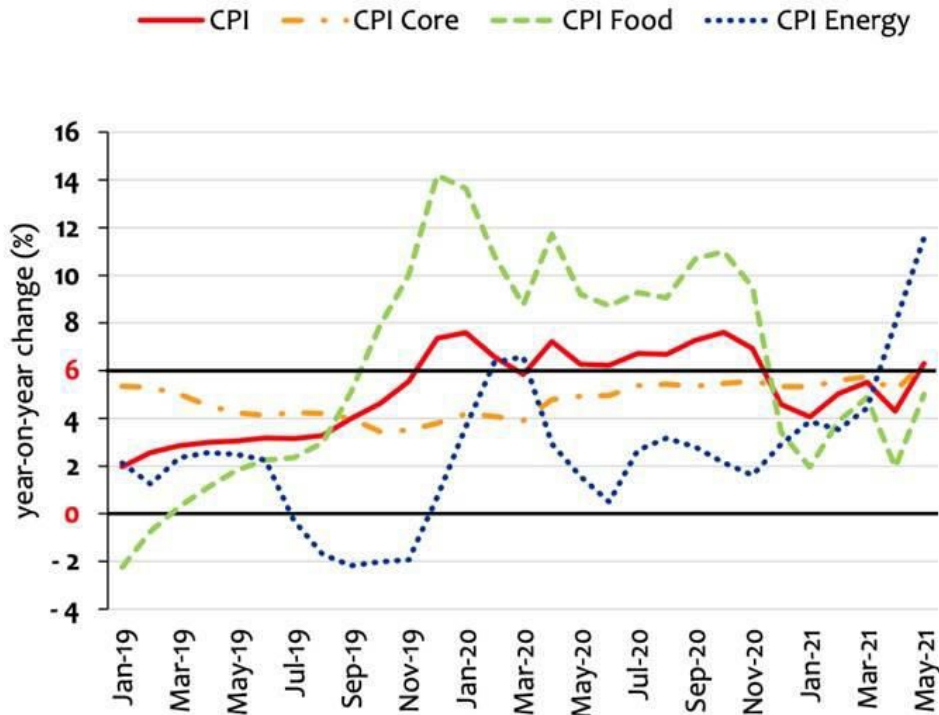
बैंकों को आने वाले महीनों में कमजोर कर्ज वृद्धि की चुनौती से भी निपटना होगा. निजी क्षेत्र का निवेश इस दौरान कम रहने से कंपनी क्षेत्र में कर्ज वृद्धि पर असर पड़ा है. बैंकिंग तंत्र में नकदी की कमी नहीं है लेकिन इसके बावजूद कंपनी क्षेत्र से कर्ज की मांग धीमी बनी हुई है. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सभी छह सदस्यों ने आम राय से रेपो में कटौती का निर्णय किया। साथ ही मौद्रिक नीति रुख तटस्थ से नरम कर दिया। समिति में गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर डा. विरल वी आचार्य, कार्यकारी निदेशक डा माइकल देवब्रत पात्रा के अलावा अन्य सदस्य डा चेतन घाटे, डा पामी दुआ, डा रविंद्र एच ढोलकिया हैं।[11,12]



आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इसका मतलब है कि ब्याज दर में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बैंक दरों में मौजूदा कटौती तथा इससे पहले फरवरी और अप्रैल में की गयी कटौती का लाभ ग्राहकों को देने में तेजी लाये।

रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए 2019-20 में जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 7.2 से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि विश्व बैंक ने इस दौरान विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। 2018-19 की आखिरी तिमाही में विकास दर 5.8 प्रतिशत ही रही है

महंगाई **काबू** **में** **रहेगी**
रिजर्व बैंक ने कहा कि 2019-20 की पहली छमाही महंगाई काबू में रहेगी। इसके अनुमान को 3 से 3.1 प्रतिशत किया गया है। यह सरकार के 2 से 6 प्रतिशत के संतोषजनक लक्ष्य के दायरे में है। अप्रैल में खुदरा महंगाई 2.92 फीसदी रही है। दूसरी छमाही में महंगाई खुदरा मुद्रास्फीति का पुर्वानुमान 3.50-3.80 प्रतिशत से घटाकर 3.40-3.70 प्रतिशत कर दिया गया।



Sources: Ministry of Statistics & Programme Implementation and Office of Economic Advisor.

रिजर्व बैंक ने उम्मीद जताई कि सरकार राजकोषीय मोर्चे पर चौकस बनी रहेगी। उम्मीद है कि सरकार 2019-20 में राजकोषीय घाटे का 3.3 फीसदी के लक्ष्य को पा लेगी, जो 2018-19 में 3.4 फीसदी पहुंच गया था।

रिजर्व बैंक एनपीए की पहचान के लिये अगले तीन-चार दिनों में संशोधित सर्कुलर जारी करेगा। अदालत ने उसके 12 फरवरी 2018 के सर्कुलर को रद्द कर दिया था। पुराने परिपत्र में बैंक कर्ज की किस्त के भुगतान में ग्राहक की ओर से एक दिन की देरी को भी एनपीए करार देने का प्रावधान था।

आईएलएफएस के बाद डीएचएफएल में संकट पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि किसी विशेष कंपनी के लिए कोई पहल नहीं की जाएगी। अगर पूरे एनबीएफसी सेक्टर में संकट आता है तो केंद्रीय बैंक कदम उठाने को तैयार है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये बृहस्पतिवार को अपनी मुख्य नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की कटौती की। साथ ही आगे के लिए नीतिगत रुख को 'तटस्थ' से 'नरम' कर दिया। नीतिगत रुख में इस बदलाव से संकेत मिला है कि कर्ज सस्ता करने के लिए केंद्रीय बैंक नीतिगत दर में और कटौती कर सकता है।

पिछले पंच महीनों में उधारी दर यानी रेपो दर में यह तीसरी कटौती है। इससे बैंकों के धन की लागत कम होने और उनकी ओर से मकान, कारोबार और वाहनों के कर्ज पर मासिक किस्त (ईएमआई) कम किए जाने की संभावना है। साथ ही कंपनियों पर कर्ज लौटाने का बोझ कम होगा।[10,11]

पिछले कुछ सालों के दौरान निजी क्षेत्र का निवेश काफी कम बना हुआ है और अर्थव्यवस्था को उठाने का काम सार्वजनिक व्यय के दारोमदार पर टिका है। बैंकिंग क्षेत्र का जहां तक सवाल है वर्ष के शुरुआती महीनों में ही कोरोना वायरस के प्रसार से उसके कामकाज पर भी असर पड़ा. गैर- निष्पादित राशि (एनपीए) यानी फेसे कर्ज से उसका पीछा छूटता हुआ नहीं दिखा.

रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अनुमान लगाया है कि मार्च 2021 तक बैंकों का सकल एनपीए 10.6 फीसदी तक हो जाएगा. वहीं शुद्ध एनपीए के 3.2 फीसदी तक होने का अनुमान है.

टाटा ग्रुप का यह स्टॉक (Tata Group stock) 4.27 रुपये के स्तर (NSE पर 1 जनवरी 1999 को बंद कीमत) से बढ़कर 2,436.55 रुपये के स्तर (NSE पर 8 फरवरी 2022 की कीमत) हो गया है। यानी 23 साल की इस अवधि में टाइटन के स्टॉक ने करीबन 57,041.69 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में इस शेयर का रेट 210.15 रुपये (4 जून 2012 का बंद भाव) से बढ़कर 2,436.55 रुपये तक पहुंच गया। दौरान इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 1,059.6 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 10 फरवरी 2017 यानी 5 साल पहले टाइटन के शेयरों की कीमत एनएसई पर 432 रुपये की थी। आज के शेयर प्राइस के हिसाब से इस शेयर ने अपने निवेशकों को करीबन 464.80 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल पर नजर डालें तो यह स्टॉक 1541.70 रुपये (8 फरवरी 2021 की NSE की क्लोजिंग प्राइस) से बढ़कर 2,436.55 रुपये (8 फरवरी 2022) पर पहुंच गया है। इस अवधि में यह शेयर 58.26 प्रतिशत भागा है। हालांकि, साल-दर-साल के हिसाब से देखें तो टाइटन के स्टॉक्स में 3.32 प्रतिशत की गिरावट है। वहीं, एक महीने में यह स्टॉक 8.19 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, आज टाइटन के शेयरों में 1.28 प्रतिशत की तेजी है।

टाइटन के शेयर प्राइस पैटर्न के मुताबिक, अगर एक निवेशक 23 साल पहले टाटा समूह के इस शेयर में ₹1 लाख का निवेश किया होता तो उसका 1 लाख आज ₹5.70 करोड़ रुपये हो जाता। अगर किसी निवेशक ने 10 साल पहले इस शेयर में 1 लाख का निवेश किया होता तो उसका 1 लाख आज 11.56 लाख रुपये हो गया होता। अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले इस मल्टीबैगर स्टॉक में ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो उसका ₹1 लाख आज ₹5.64 लाख हो जाता। इसी तरह, अगर किसी निवेशक ने 1 साल पहले इस मल्टीबैगर स्टॉक में निवेश किया होता और इस अवधि तक निवेश को बनाए रखता, तो उसका 1 लाख रुपये आज 1.58 लाख हो गया होता।

बता दें कि टाइटन शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala portfolio stock) का पसंदीदा स्टॉक्स में से एक है। टाइटन कंपनी (Titan company) के अक्टूबर-दिसंबर 2021 शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक झुनझुनवाला के पास 3,57,10,395 शेयर हैं जो 4.02 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है। वहीं, उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन के 95,40,575 शेयर यानी 1.07 फीसदी हिस्सेदारी है। झुनझुनवाला दंपति की टाइटन में 5.09 फीसदी हिस्सेदारी है। जानकारों की मानें तो शॉर्ट टर्म में टाइटन का शेयर (Titan share target price) 2,500 रुपये तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में यह 2,820 रुपये तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन के शेयर में 3 महीने में जबरदस्त कमाई की है। [9,10]

निष्कर्ष

अर्थव्यवस्था में सुधार : आरबीआई ने अपने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न अनुमानों की तुलना में तेजी से कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव से बाहर आ रही है और आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ही सकारात्मक दायरे में आ जाएगी.

कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 23.9 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आयी. वहीं दूसरी तिमाही में गिरावट कम होकर 7.5 प्रतिशत रही.

हालांकि इसी के साथ एक लेख में आरबीआई विशेषज्ञों ने केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक विकास की गति को बरकरार रखने के लिए राजकोषीय उपायों को जारी रखने की सलाह दी है.[11]

गौतम अडानी (Gautam Adani) अब मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति (Asia's Richest Person) बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स (Bloomberg Billionaires Index) के मुताबिक, 59 साल के अडानी

की नेटवर्थ 88.5 अरब डॉलर पहुंच चुकी है जबकि अंबानी की नेटवर्थ 87.9 अरब डॉलर है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, अडानी की संपत्ति में 12 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। इसी के साथ अडानी इस साल दुनिया में सबसे तेज कमाई करने वाले अरबपति बन गए हैं। वहीं, अंबानी की नेटवर्थ में 2.07 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बनने के साथ ही दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में भी आ गए हैं, जबकि मुकेश अंबानी इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। अमीरों की इस लिस्ट में अंबानी 11वें नंबर पर आ गए हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 235 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। गौतम अडानी ने एक छोटी सी कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी से व्यापार की शुरुआत की थी, जिसका उन्होंने कई बंदरगाहों, खानों और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में विस्तार किया। वर्तमान में अडानी का बिजनेस पोर्ट्स, माइन्स, ग्रीन एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में है। गौतम अडानी ने नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में व्यापार विस्तार किया साथ ही एयपोर्ट्स, डेटा सेंटर और रक्षा सौदों में कारोबार बढ़ाया। पिछले 2 साल में अडानी की कंपनी के शेयरों में करीबन 600% का इजाफा हुआ है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के मजबूत तिमाही नतीजों के बाद शुक्रवार को बैंक के शेयरों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 549 रुपये के अपने 52 हफ्ते के हाई को छुआ है। हालांकि, उसके बाद से बैंकिंग स्टॉक थोड़े 'दबाव' में हैं। लेकिन, मार्केट एक्सपर्ट्स पब्लिक सेक्टर बैंक पर काफी बुलिश हैं। इसी तरह, प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक के तिमाही नतीजे मजबूत रहे हैं। हालांकि, अभी ICICI बैंक के शेयर अपने 867 रुपये के 52 हफ्ते के हाई से करीब 85 रुपये नीचे हैं।

स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स (SBI और ICICI बैंक) के तीसरी तिमाही के नतीजे मजबूत रहे हैं और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि, जब एक्सपर्ट्स से इन दोनों स्टॉक में से कोई एक चुनने के बारे में पूछा गया तो खरीदने के लिए PSU बैंकिंग स्टॉक उनका फेवोरिट रहा। हाल ही में पेश किए गए बजट 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी अधिक फोकस किया गया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

प्रॉफिटमार्ट सिक्वोरिटीज में रिसर्च के हेड अविनाश गोरक्षकर का कहना है, 'एसबीआई और ICICI बैंक दोनों के ही दिसंबर 2021 तिमाही के नतीजे मजबूत रहे हैं। अनलॉक एक्टिविटीज के साथ ही दोनों बैंकों के बिजनेस वॉल्यूम में उछाल आने की उम्मीद है। हालांकि, इंफ्रा-फोकस्ड बजट 2022 के बाद SBI को क्रेडिट लाइन के लिए और डिमांड देखने को मिल सकती है, जिससे ICICI बैंक के मुकाबले PSU बैंक का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा।' गोरक्षकर का कहना है कि इनवेस्टर्स को 650 रुपये के लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ SBI के शेयरों को होल्ड करना चाहिए। [12]

संदर्भ

- 1) Great Depressions of the Twentieth Century, edited by T. J. Kehoe and E. C. Prescott 2000
- 2) Theories of the Great Depression, R. L. Norman, Jr.2001
- 3) America in the 1930s. Very large multi-mediated project on America in the Great Depression
- 4) Recession? Depression? What's the difference? (About.com)2005
- 5) An Overview of the Great Depression from EH.NET by Randall Parker.2006
- 6) Great Myths of the Great Depression by Lawrence Reed 2009
- 7) Franklin D. Roosevelt Library & Museum for copyright-free photos of the period1999
- 8) Economic Depressions: Their Cause and Cure by Murray Rothbard (1969)
- 9) The Impact of the Great Depression in NI, on the Second World War online resource for NI 1997
- 10) Great Depression in the Deep South 1996
- 11) Lessons from the 1929 Crash and the Great Depression 2000
- 12) How to to avoid a 2008 Remake of the Keynesian Debacle



**Impact Factor:
7.569**



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details